शिक्षक - रवि शंकर राय विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 13-08-2020 वर्ग - B.A - II

नई औद्योगिक नीति, 1991

(New Industrial policy, 1991)

भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे और इसकी प्रकृति को आकार पूर्व की औद्योगिक नीतियों की वजह से ही मिला है। समय की मांग थी कि नब्बे के दशक की शुरुआत में इसकी प्रकृति और ढांचे को बदला जाए। भारत सरकार ने औद्योगिक नीति के मूल स्वरूप को बदलने का फैसला किया जिससे खुद-ब-खुद अर्थव्यवस्था की प्रकृति और कार्यक्षेत्र बदलाओं की ओर अग्रसर होंगे। इस तरह 1991 की नई औद्योगिक नीति आई।

इस नीति के साथ सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को शुरू किया, इसलिए इस नीति को एक नीति के बजाय प्रक्रिया ज्यादा माना गया।

जून 1991 में भारत के लिए एक गंभीर भुगतान संकुलन का संकट था। 1990 तथा 1991 में अनेक परस्पर जुड़ी हुई घटनाएँ हुई, जो भारत के आर्थिक हित के विपरीत थीं—

i) खाड़ी युद्ध (1990-1991) के कारण तेल की बढ़ती कीमत भारत की विदेशी मुद्रा को तेज गति से खाली कर रही थी।

ii) विदेश में खासकर खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों द्वारा भेजे गए धन में खाड़ी युद्ध के कारण आई गिरावट।

iii) मुद्रास्फीति दर लगभग 17% पहुँच गयी थी।

iv) केन्द्र सरकार का सकल वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 8.4% था।

v) जून 1991 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घट कर मात्र दो सप्ताह के आयात के लिए ही पर्याप्त रह गया था।

1991 में भारत सरकार द्वारा बाजार उदारीकरण के लिए उठाए गए कदम का मुख्य कारण गंभीर भुगतान संतुलन का संकट था तथा सरकार ने इस संदर्भ में एक क्रमित नीति अपनाई। चूंकि आर्थिक सुधार का मुख्य कारण भुगतान संतुलन का संकट था, इसलिए इसके प्रारंभिक चरण ने व्यष्टि आर्थिक स्थिरीकरण (~~Mac~~ पर बल दिया, वहीं औद्योगिक नीति, व्यापार तथा विनिमय दर नीति, विदेशी निवेश नीति, वित्तीय तथा कर सुधार तथा सार्वजनिक क्षेत्र सुधार के उपायों को शीघ्र ही इसके बाद लागू किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को 1990-91 के भुगतान संतुलन संकट से लड़ने के लिए वित्तीय सहायता दी गयी। इसके बदले में सरकार को कुछ शर्तों को पूरा करना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यह शर्त थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संरचनात्मक पुनः सामंजस्य हो। इस समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊँची

एवं श्रम को विभिन्न औद्योगिक नीतियाँ प्रवाहित करती थी इसलिए आर्थिक संरचना में परिवर्तन के लिए यह आवश्यक था कि इसे एक नई औद्योगिक नीति द्वारा परिभाषित किया जाय। 23 जुलाई, 1991 को सरकार द्वारा घोषित की गई नई औद्योगिक नीति ने देश में एक वृहत आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत की जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक पुनः समायोजन था ताकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की शर्तों को पूरा किया जा सके। इस नीति के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं —

1. उद्योगों को अनारक्षित करना

i) नाभिकीय अनुसंधान तथा संबद्ध गतिविधियाँ, जैसे रेडियोधर्मी खनिजों का खनन, उपयोग, प्रबंधन, ईंधन निर्माण, निर्यात–आयात, अपशिष्ट प्रबंधन, इत्यादि।

ii) रेल सेवा (रेल सेवा से संबद्ध अनेक कार्यों के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान की गई है; लेकिन अभी भी निजी कंपनियाँ इस क्षेत्र में एक पूर्ण विकसित रेल सेवा प्रबंधक के रूप में प्रवेश नहीं कर सकती हैं।)

2. उद्योग के लिए लाइसेंसिंग हटाना — (De-licencing of the Industries) —

इन उद्योगों की संख्या घटाकर मात्र 18 कर दी गई, जिसके लिए अनिवार्य लाइसेंस जरूरी था। (1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के तहत अनुसूची B तथा C में दर्ज उद्योग)। इस क्षेत्र में आर्थिक सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया तथा वर्तमान में मात्र 5 उद्योग ऐसे हैं जिसके लिए अनिवार्य लाइसेंस की जरूरत है —